प्रकाशन का 47 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 28 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 04 – 11 जुलाई 2022 मूल्य पांच रूपए

भाजपा के आतंकियों व अपराधियों से संबध–कांग्रेस का बडा आरोप

शिमला/शैल। कांग्रेस जिस स्तर पर अब भाजपा के खिलाफ आक्रामक हो गयी है उसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन अभी कांग्रेस के आरोपों ने भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे पर जिस तरह के आरोप लगाते हुये प्रश्न उठाये हैं उनके दंश से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा के पैगम्बर मोहम्मद पर दिये बयान पर जिस तरह की अंतरराष्ट्रीय जगत में प्रतिक्रियाएं उभरी उनका संज्ञान लेते हुए पार्टी ने उन्हें न केवल प्रवक्ता के दायित्व से मुक्त कर दिया बल्कि पार्टी से भी निलंबित कर दिया। लेकिन पार्टी की इस कारवाई के बाद नुपूर शर्मा के पक्ष और विरोध में लंबी लाइनें खड़ी हो गयी। इसी परिदृश्य में महाराष्ट्र और उदयपुर की घटनायें घट गयी। उदयपुर की घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो गया। ज़ी न्यूज ने अपने डीएनए प्रोग्राम में इसे प्रसारित भी कर दिया। जी न्यूज के प्रसारण के बाद पूर्व सूचना एवं प्रसारण मन्त्री राज्यवर्धन राठौर जैसे भाजपा नेताओं तक ने भी इसे प्रचारित कर दिया। राहुल गांधी का यह वीडियो फेक था। इससे बायनाड में दिये एक बयान में कांट छांट करके तैयार किया गया था। मकसद राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने का था। जैसे ही जी न्यूज़ का प्रसारण कांग्रेस के संज्ञान में आया तो पूरी पार्टी में रोष फैल गया। जी न्यूज़ का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव तक कर दिया। जी न्यूज़ ने इस फर्जी वीडियो के प्रसारण के लिये क्षमा–याचना करते हुए इसे हटा लिया। सर्वोच्च न्यायालय में भी क्षमा याचना करने का पक्ष रखा और कहा कि उसे यह ए एन आई न्यूज़ से मिला। लेकिन कांग्रेस ने इस तरह के फर्जी वीडियो प्रसारित कर उनके नेताओं की छवि खराब करने के प्रयासों को गंभीरता से लेते हुए इसे कानूनी अंजाम तक ले जाने के लिये जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन और पूर्व मंत्री राज्यवर्धन राठौर के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करवा दिये हैं। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि ऐसे सारे प्रयासों का इस तरह से जवाब दिया जायेगा। स्मरणीय है कोबरा पोस्ट अपने एक स्टिंग ऑपरेशन में बहुत पहले यह खुलासा देश के सामने रख चुका है कि कैसे मीडिया घरानों और न्यूज़ चैनल को पैसे देकर राहुल गांधी और दूसरे नेताओं की छवि खराब करवाई जा रही है। अब जिस ढंग से जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन बेनकाब हुए हैं और अपने कृत्य के लिये क्षमा याचना की उससे कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन को भी स्वत: ही अधिमान मिल जाता है। उदयपुर की जिस घटना के साथ राहुल गांधी का बयान जोड़ा जा रहा था उसका आरोपी भाजपा का कार्यकर्ता निकला है। इसी तरह जम्मू–कश्मीर में पकड़े गये दो आतंकियों में से एक भाजपा का पदाधिकारी निकला है। कांग्रेस ने 2017 से लेकर अब तक घटे कुछ प्रमुख प्रकरण को देश की जनता के सामने रखते हुये भाजपा से तीखे सवाल पूछे हैं। इस संबंध में देश के हर राज्य में कांग्रेस ने वाकायदा पत्रकार वार्ताएं आयोजित करके जनता को जागरूक करने की रणनीति बना रखी है। इसके लिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ओर से एक प्रैस बयान जारी किया गया है। भाजपा की ओर से कांग्रेस के इन आरोपों का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कांग्रेस का बयान यथास्थिति पाठकों के सामने रखा जा रहा है।

श्री पवन खेड़ा द्वारा जारी वक्तव्य

आतंकवादियों से नाता है

यह रिश्ता क्या कहलाता है

पिछले एक सप्ताह में घटी दो घटनाओं ने भाजपा के चाल,चरित्र और चेहरा को बेनकाब कर दिया है। पहले उदयपुर हत्याकांड में शामिल एक आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। उसके बाद जम्मू-कश्मीर में पकड़े गए लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादियों में से एक "तालिब हुसैन शाह" बीजेपी का पदाधिकारी निकला जिसकी देश के गृह मंत्री के साथ तक तस्वीर है। जब ये पकड़ा गया तब पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं पर हमले की योजना बना रहा था।

सोचिए, राष्ट्रवाद की बात करने वालों के लिए क्या ये शर्म की बात नहीं है? और ये कोई पहला या दूसरा मौका नहीं है जब भाजपा के नेता या कार्यकर्ता आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं।

- क़रीब दो साल पहले जम्मू कश्मीर में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। जब आतंकियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में बीजेपी के पूर्व नेता एवं सरपंच "तारिक़ अहमद मीर" को गिरफ्तार किया गया था। अहमद पर हिजबुल कमांडर नवेद बाबू को हथियार देने का आरोप था जो आतंकियों की मदद करने वाले डीएसपी दविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार हुआ था। एनआईए ने साफ तौर पर कहा भी था कि "तारिक़ अहमद मीर" दविंदर सिंह का सहयोगी है। यदि दविंदर सिंह के मामले की ढंग से जांच होती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता लेकिन जांच बीच में ही रोक दी गई।

- साल 2017 में मध्यप्रदेश की वो घटना आपको याद होगी जब एटीएस की टीम ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश करते हुए ISI के 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इनमें एक बीजेपी आईटी सेल का सदस्य ध्रुव सक्सेना भी शामिल था। जिसकी राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तस्वीर वायरल हुई थी।

- इसके 2 साल बाद मध्यप्रदेश में बजरंग दल के एक नेता बलराम सिंह की गिरफ्तारी टेरर फंडिंग के आरोप में हुई थी।

- वर्ष 2017 में एनआईए की विशेष अदालत ने आतंकियों को आर्थिक मदद देने के आरोप में असम के भाजपा नेता "निरंजन होजाई" को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इन्हें एक हजार करोड़ के वित्तीय घोटाले एवं टेरर फंडिंग मामले में दोषी पाया गया था। इनकी फंडिंग से मिले पैसों से आतंकवादी हथियार आदि खरीदते थे जिसका इस्तेमाल देश की सेवा में लगे हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ होता था।

- इतना ही नहीं बीजेपी सत्ता के लिए अपराध सिद्ध आतंकवादी को भी टिकट देने से नहीं चुकी है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने मसूद अजहर के शागिर्द "मोहम्मद फारुख खान" को स्थानीय चुनाव में श्रीनगर के वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया था। जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एवं हरकत उल मुजाहिदीन का सदस्य रह चुका है।

ऐसे में हम मीडिया के माध्यम से देश के लोगों से अपील करते हैं कि आप भाजपा के खोखले राष्ट्रवाद को पहचानिए। राष्ट्रवाद की आड़ में ये देश को खोखला करने का घिनौना खेल खेल रहे हैं।

नूपुर शर्मा भी आपकी पार्टी की और रियाज़ अटारी भी आप ही की पार्टी का? तालिब हुसैन भी आपकी पार्टी का? खुद मेन्स्ट्रीम में रहने के लिए ऐसे कितने फ्रिंज पाले हैं आपने?

अब हिमुडा की कार्यप्रणाली आयी सवालों में

18 वर्ष पहले खरीदी संपत्ति पर आज तक कब्जा नहीं हो पाया

शिमला/शैल। हिमुडा ने वर्ष 2004–05 में राजधानी शिमला के धोबी धाट क्षेत्र में एक कालोनी बनाने के लिये जमीन खरीदी थी। इसमें कुछ खाली जमीन थी और कुछ मकान थे। इसमें एक मकान हार्डिंगंज विला के नाम से था। यह मकान दो भाइयों जीत और जोगिंदर का था। इसी के कुछ भाग में सुधीर नाम का एक किराएदार था और आऊट हाऊसिंग वाले भाग में पुलिस के वायरलेस विंग में कार्यरत अधिकारी कालिया किराएदार थे। हिमुडा के नाम रजिस्ट्री होने के बाद कालिया मकान छोड़ कर चले गये। लेकिन दूसरे किराएदार सुधीर ने कब्जा नहीं छोड़ा। अब सुधीर की मृत्यु के बाद उसके बेटों ने न केवल मकान की रिपियर ही करवा ली बल्कि कालिया और जोगिंदर वाले हिस्से पर भी कब्जा कर लिया है। मकान की रिपेयर करवा कर यह जताने का प्रयास किया है कि यह उन्हीं की संपत्ति है। यह रकवा करीब 1 बीघा है। जिसकी कीमत 5 से 6 करोड़ मानी जा रही है। हिमुडा की प्लान के मुताबिक इस मकान को तोड़कर कालोनी के लिये सड़क बनायी जानी थी। जिसकी चढ़ाई चार से पांच मीटर प्रस्तावित थी और यह अभी तक नहीं बनी है। एक बार नगर निगम ने सड़क बनाने का प्रयास किया लेकिन हिमुडा ने ही इसे गिरा दिया। यहां पर बनी हिमुडा कालोनी का एक संगठन भी बना हुआ है। जिसका अध्यक्ष भी शायद सुधीर परिवार से ही ताल्लुक रखता है। यहीं पर जोगिंदर के केयरटेकर एक नन्दा शर्मा मजदूर थे। इस नन्दा शर्मा से मकान खाली करवाने के आदेश हिमुडा प्राप्त कर चुकी है। लेकिन सुधीर के बेटों के खिलाफ कोई कारवायी नहीं करवा पायी है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब एक मजदूर से मकान खाली करवाने के आदेश पाने में हिमुडा सफल हो गया है तो दूसरे लोगों से ऐसा क्यों नहीं करवा पाया है। इस बारे में जब हिमुडा कार्यालय में बात की गयी तो प्रशासनिक अधिकारी को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने इस बारे में संबंधित अभियन्ता से बात करने को कहा जो कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं था। यह मकान और जमीन 18 वर्ष पहले खरीदे गये थे। परंतु इनका पूरा कब्जा हिमुडा आज तक हासिल नहीं कर पायी है। यह एक व्यावहारिक सच है। ऐसा क्यों नहीं हो पाया है? क्या इसमें हिमुडा के अधिकारियों की ही नाकामी रही है या इस पर कोई और दबाव रहा है? क्योंकि यह कैसे संभव हो सकता है कि 18 वर्षों में हिमुडा मुख्यालय के संज्ञान में यह मामला ही नहीं आया हो और प्रशासनिक अधिकारी तक को इसकी जानकारी न रही हो।

राज्यपाल ने सब-जूनियर वुशू प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मण्डी के पढढल खेल मैदान में 22वें सब-जूनियर राष्ट्रीय वुशू प्रतियोगिता 2022 का शुभारम्भ किया। उन्होंने इस अवसर पर वुशू खेल को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि यह खेल न केवल शारीरिक क्षमता को सुधारने का कार्य करता है, बल्कि इससे व्यक्ति अनुशासित भी बनता है। यह प्रतियोगिता भारतीय वुशू संघ और हिमाचल प्रदेश वुशू संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है।

आर्लेकर ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभा वास्तव में प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि अनुशासन की कमी के कारण समाज में कई समस्याएं हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों द्वारा दिखाया गया अनुशासन प्रेरणादायक है।

उन्होंने कहा कि वुशू न केवल एक खेल है, बल्कि आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि इससे व्यक्ति में आत्म-अनुशासन का विकास होता है।

उन्होंने भारतीय वुशू संघ और राज्य वुशू संघ के प्रयासों की सराहना की और संतोष व्यक्त किया कि राज्य की युवा पीढ़ी इस खेल को अपना रही है और बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में भाग ले रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ओलंपिक खेलों में भी वुशू को शामिल करने के प्रयास कर रही है।

उन्होंने इस अवसर पर औपचारिक रूप से प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया, जिसमें 33 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के 1300 खिलाड़ी इस पांच दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं।

स्पेशल ओलंपिक इंडिया की अध्यक्षा डॉ. मलिका नड्डा ने वुशू प्रतियोगिता में देश भर से आये खिलाड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस खेल के बारे में बहुत कम लोग अवगत थे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश की भावी पीढ़ी को यह कला सिखाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक इस खेल के खिलाड़ियों ने चार अर्जुन पुरस्कार और एक द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है और 'खेलो इंडिया' के माध्यम से भी इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है।

डॉ. मलिका नड्डा ने कहा कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष और पैरालिंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से विशेष और पैरालिंपिक के खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम बनाने का आग्रह किया ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने के लिए उचित स्थान मिल सके।

इससे पूर्व पढढल मैदान पहुंचने पर राज्यपाल को भारतीय वुशू संघ द्वारा पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने खेल का झंडा फहराया।

राज्यपाल ने इस अवसर पर डेमो फाइट का भी आनंद लिया। इस अवसर पर विभिन्न आयु वर्ग के वुशू पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

इससे पूर्व आयोजन समिति के उपायुक्त एवं अध्यक्ष अरिंदम चौधरी ने भी राज्यपाल को हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।

हिमाचल प्रदेश वुशू संघ के महासचिव पी.एन. आजाद ने राज्यपाल का स्वागत किया और संघ की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी तथा इस अवसर पर प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी दी।

हिमाचल प्रदेश वुशू संघ के अध्यक्ष शिवपाल मनहंस ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

मुख्यमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयन्ती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी शिमला मण्डल द्वारा खलीनी में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन भारत की एकता और अखण्डता के लिए समर्पित कर दिया। उनके उच्च आदर्शों ने देशवासियों को हमेशा ही प्रेरित किया है।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्धाज ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उच्च आदर्श, विचार और लोगों के प्रति सेवा भावना हमें निरन्तर प्रेरित करती रहेगी।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद की महासचिव पायल वैद्य, भाजपा मण्डलाध्यक्ष राकेश शारदा, प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा संजीव देस्टा, भाजपा के संगठन पदाधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पठानकोट-मण्डी फोरलेन परियोजना 21 महीने की अवधि के भीतर पूरी हो जाएगी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने एनएच-20 (नया एनएच-154) के पठानकोट-मण्डी सेक्शन के थानपुरी से परौर सेक्शन के पुनर्वास और उन्नयन के लिए 815.686 करोड़ रुपये स्वीकृत करने पर केन्द्र सरकार और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह परियोजना 21 महीने की अवधि के भीतर पूरी हो जाएगी और इससे यात्रियों का समय बचने के अलावा उन्हें आरामदायक यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन के साधन सीमित होने से हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए सड़कों को जीवन रेखा माना जाता है और राज्य सरकार सड़कों और पुलों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने दलाई लामा को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी

शिमला/शैल। तिब्बती धर्मगुरू परम पावन दलाई लामा के जन्म दिवस के अवसर पर कांगड़ा जिला के धर्मशाला में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर शिमला से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुये।

धर्मशाला में आयोजित दलाई लामा जी के जन्मदिन समारोह में मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का पूर्व निधारित कार्यक्रम था, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण इस तय कार्यक्रम में वह वर्चुअल माध्यम से शामिल हुये। उन्होंने परम पावन दलाई लामा से दूरभाष के माध्यम से बातचीत की और उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु की कामना की।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परम पावन दलाई लामा मानवता और अध्यात्म को लेकर जिस ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं, वह भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि दलाई लामा का सम्पूर्ण जीवन मानवता, शान्ति और अहिंसा के लिए समर्पित है। उन्होंने तिब्बत के लोगों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तिब्बत के मुद्दों के समाधान के लिये दलाई लामा जी के अहिंसक प्रयास दुनिया के लिए उदाहरण है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला को बौद्ध धर्म की पवित्र नगरी और दलाई लामा के घर के रूप में जाना जाता है। यह शहर पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जय राम ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में जब लोगों के मन में वैक्सीन लगाने को लेकर कई तरह के भ्रम थे, उस समय दलाई लामा जी ने स्वयं वैक्सीन लगवाकर इन भ्रान्तियों को दूर करने का कार्य किया और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से दलाई लामा के विचारों को अपने जीवन में अपनाने का आहवान करते हुए पूरी मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने का आग्रह किया।

इस अवसर पर शिमला में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभासीष पन्डा, मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं प्रधान निजी सचिव डॉ. आर.एन बत्ता, सी.टी.ए. के शिमला में प्रतिनिधि अधिकारी टी. दोरजे, मुख्य सलाहकार तेनजिन और प्रभारी लामा याफफिल एबोट उपस्थित थे।

हड़ताल पर गए पंचायत सचिवों का कार्यभार ग्राम रोजगार सेवकों, सिलाई अध्यापिकाओं एवं पंचायत चौकीदारों को सौंपने के निर्देश

शिमला/शैल। निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज रुग्वेद ठाकुर ने जानकारी दी कि जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विभाग द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों का कार्य सुचारू रूप से चलाने, ग्रामीण जनता को विभिन्न प्रमाण पत्रों जैसे जन्म-मृत्यु, विवाह, बीपीएल तथा अन्य पंचायत रिकॉर्ड की प्रतिलिपियां प्रदान करने के दृष्टिगत विभाग द्वारा अतिरिक्त जिला उपायुक्तों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को यह निर्देश जारी किये गए हैं कि हड़ताल पर गए पंचायत सचिवों का कार्यभार ग्राम रोजगार सेवकों, दसवीं पास या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाली सिलाई अध्यापिकाओं तथा पंचायत चौकीदारों को तुरन्त प्रभाव से सौंपा जाए। जिलों द्वारा इस सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

निदेशक पंचायती राज ने यह भी जानकारी दी कि सरकार द्वारा हाल ही में 389 पंचायत सचिवों के पदों का सृजन किया गया है। इन पदों को शीघ्र भरने के लिए विभाग द्वारा तत्परता से कार्य किया जा रहा है ताकि रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जा सके और पंचायत के कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिवों के 239 पद भरने की प्रक्रिया पहले ही जारी है तथा तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा 20, 21 तथा 22 जुलाई, 2022 को टंकण परीक्षा के लिए तिथियां निर्धारित की गई हैं। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत शीघ्र ही 239 पंचायत सचिव पंचायतों में नियुक्ति के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। तकनीकी सहायकों के नव-सृजित 124 तथा पहले से ही रिक्त 40 पदों की भर्ती प्रक्रिया उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा शीघ्र आरम्भ कर दी जाएगी।

रुग्वेद ठाकुर ने बताया कि सरकार हड़ताली कर्मचारियों की वजह से उत्पन्न हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कारगर कदम उठा रही है, ताकि ग्रामीण जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

भूजल उपयोगकर्ता 31 अगस्त तक करवाएं पंजीकरण

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में सभी मौजूदा भूजल उपयोगकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश भूजल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत 31 अगस्त, 2022 तक अपने मौजूदा भूजल संरचनाओं को फॉर्म-4 और 4-ए पर www.emerging himachal.hp.gov.in. या हिमाचल प्रदेश भूजल प्राधिकरण के पोर्टल www.hpiph.org. के माध्यम से पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भूजल के सभी मौजूदा उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस अंतिम अवसर का लाभ उठाएं व पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए www.emerging himachal.hp.gov.in or www.hpiph.org पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त, 2022 या उससे पहले करें, उसके पश्चात भूजल प्राधिकरण के पोर्टल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और 31 अगस्त, 2022 के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसके उपरांत मौजूदा टयूब बेल, बोर वेल और सक्रिय हैंड पम्प (घरेलू, सिंचाई, वाणिज्यक और औद्योगिक उद्देश्यों) जो हिमाचल प्रदेश ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी शिमला के साथ पंजीकृत नहीं हैं, के अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ हिमाचल प्रदेश भूजल (विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2005 और नियम, 2007 की विभिन्न धाराओं के तहत उचित कारवाई की जाएगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
अंजना

हिमाचल को स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में एस्पायरिंग लीडर का खिताब मिला

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी दी की हिमाचल

प्रदेश को राज्य में मजबूत स्टार्टअप ईको सिस्टम विकसित करने के लिए एस्पायरिंग लीडर के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021 आयोजित समारोह में हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग को यह सम्मान प्रदान किया गया।

उन्होंने कहा कि मजबूत स्टार्टअप प्रणाली तैयार करने के लिए की गई नवाचार पहलों, स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरल सार्वजनिक खरीद नियम बनाने, हिम स्टार्टअप योजना आरम्भ करने और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों को सराहा गया।

उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव राम सुभग सिंह को नए स्टार्टअप आरम्भ करने के लिए राज्य अनुमोदन व स्वीकृतियां प्रदान करने और स्टार्टअप के लिए इन्क्यूबेटर को फंड प्रदान करने के उद्देश्य से हिमसुप योजना शुरू करने के लिए उनके द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों के लिए उपलब्धि प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति को प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेनडेशन से सम्मानित किया गया।

उद्योग विभाग की संयुक्त निदेशक दीपिका खतरी को स्टार्टअप योजना के बारे में जागरूकता फैलाने और राज्य में उद्योगों के लिए प्लग एवं प्ले सुविधा प्रदान करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेनडेशन प्रदान किया गया।

एनएफएसए के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल ने प्राप्त किया दूसरा स्थान

शिमला/शैल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश ने

विशेष श्रेणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के लिए यह गौरव की बात है कि छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया और लॉजिस्टिक की कमी के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने सामान्य श्रेणी के राज्यों को भी कड़ी प्रतिस्पर्धा दी।

केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा विषय पर नई दिल्ली में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया।

राजिन्द्र गर्ग ने कहा कि राज्य में लगभग 30 लाख लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत कवर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य रैंकिंग सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एनएफएसए में किये गये सुधारों के आधार पर जारी किया गया है। इससे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य राज्यों में किए गए सुधार कार्यों से सीखने का अवसर मिलेगा।

राजिन्द्र गर्ग ने कहा कि यह रैंकिंग सूचकांक तीन स्तंभों पर आधारित है जिसमें खाद्य सुरक्षा और पोषण के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता हैं।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल भवन चंडीगढ़ में सम्मेलन हॉल समर्पित किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल भवन, चंडीगढ़ में लगभग 43.27 लाख रुपये की लागत

से निर्मित सम्मेलन हॉल जनता को समर्पित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 33 प्रतिभागियों की क्षमता के इस हॉल में आधुनिक ध्वनि प्रसार संयन्त्र और डिसप्ले स्क्रीन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी संवाद और बैठकों का प्रचलन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसी के दृष्टिगत आधुनिक सुविधाओं से युक्त आधारभूत ढांचे के सृजन पर विशेष बल दिया जा रहा है।

कोविड संकटकाल के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा अधिकांश बैठकों का संचालन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया और सभी दायित्वों का निर्वहन बखूबी सुनिश्चित हुआ। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक ने कार्यपद्धति को बदला है और इससे समय की बचत भी सुनिश्चित हो रही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित किए जा रहे अधिकांश कार्यालय भवनों और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में नवीनतम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर विशेष बल दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह इमारतें इको-फ्रेंडली होने के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूर्ण करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल भवन, चंडीगढ़ में इस सम्मेलन हॉल से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, चंडीगढ़ में बसे हिमाचलवासियों, विभिन्न संघों, प्रेस व मीडिया सहित अन्य लोगों को भी अपनी बैठकों व सम्मेलनों के आयोजन के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें पर्यटन निगम की विभिन्न नवोन्मेषी परियोजनाओं की जानकारी प्रदान की।

मुख्य सचिव की नाबार्ड के अध्यक्ष के साथ बैठक

शिमला/शैल। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ.जी.आर.चिंताला के साथ एक बैठक की, जिसमें हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय

कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अन्तर्गत चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं के बारे में चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि नाबार्ड के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को जमीनी स्तर पर 20260.14 करोड़ रुपये ऋण प्रवाह (क्रेडिट फ्लो) जबकि कृषि क्षेत्र में 8855.60 करोड़ रुपये ऋण प्रवाह रहा। वर्ष 2021-22 में वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत नाबार्ड की उपलब्धि 77.98 प्रतिशत रही।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अन्तर्गत 4.36 लाख किसानों को कवर किया जा चुका है और केसीसी के तहत पांच लाख से अधिक और किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021-22 में राज्य में फसल ऋण के रूप में लगभग 7296.17 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं और वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित ऋण संभावना 29172.00 करोड़ रुपये लक्षित की गई है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ) के तहत पॉलीहाउस, रोपवे और सीवरेज परियोजनाओं की स्थापना सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 1134 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों और नाबार्ड के अधिकारियों को कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कहा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) और प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों (पीडब्ल्यूसीएस) को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा।

बैठक में प्रधान सचिव आर.डी. नज़ीम, प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव अमिताभ अवस्थी, सचिव डॉ.अजय कुमार शर्मा, हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड के महाप्रबंधक डॉ. सुधांशु के.के. मिश्रा, विशेष सचिव राकेश कंवर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

गौसदनों का कार्य शीघ्र पूर्ण करें:वीरेंद्र कंवर

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग की एक समीक्षा बैठक यहां आयोजित की गई।

बैठक में प्रदेश में पशुपालकों के हित में चलाई जा रही केन्द्र प्रायोजित तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।

बैठक को सम्बोधित करते हुए वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए कृतसंकल्प है और वर्तमान प्रदेश सरकार के प्रयासों से गौशालाओं तथा गौसदनों में गौवंश की संख्या 6 हजार से बढ़कर 20 हजार से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में प्रदेश में पांच बड़े गौ अभयारण्यों एवं गौसदनों की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त हिमाचली पहाड़ी गाय के संरक्षण के लिए उत्कृष्ट फार्म स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौसदनों में आश्रित गौवंश के लिए गोपाल व्यवस्था के अन्तर्गत अनुदान राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

पशुपालन मंत्री ने प्रदेश में स्थापित किए जा रहे ऐसे सभी गौसदनों, जिनके लिए धनराशि गौसेवा आयोग के माध्यम से जारी की जा चुकी है, उनका कार्य शीघ्र पूर्ण करने के उपरांत इन्हें निर्धारित समयावधि में क्रियाशील करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने पशुपालकों के लिए कई योजनाएं प्रारम्भ की हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी निष्ठापूर्वक एवं लगन के साथ इन विभागीय योजनाओं का लाभ समयबद्ध सभी पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

बैठक में सचिव पशुपालन डॉ. अजय शर्मा ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से चर्चा के उपरांत विभागीय गतिविधियों का मूल्यांकन किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विभागीय स्तर पर और तेजी लाई जाएगी।

निदेशक पशुपालन विभाग डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। बैठक में सभी जिलों के विभागीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। .....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

घातक होगी धार्मिक श्रेष्ठता को लेकर उभरी है हिंसा

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिन की बैठक के बाद यह ब्यान आया है कि आने वाले तीस चालीस वर्ष भाजपा के ही होंगे। आज भाजपा को देश की सत्ता संभाले आठ वर्ष हो गये हैं। यदि इन आठ वर्षो का आकलन किया जाये तो महंगाई और बेरोजगारी इस काल में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ गयी है। डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुका है। नॉन ब्रैण्डिंग खाद्यान्न पर भी 5 से 18% तक जीएसटी ही लग चुका है। रसोई गैस के दामों में भी 50 रूपये की बढ़ौतरी हो गयी है। पेट्रोल डीजल के दामों में कब कितनी बढ़ौतरी हो जाये यह आशंका लगातार बनी हुई है। विदेशी निवेशक लगातार शेयर बाजार से अपना निवेश निकलता जा रहा है। केंद्र से लेकर राज्यों तक सरकारें किस हद तक कर्ज के चक्रव्यूह में फंस चुकी है यह आरबीआई द्वारा चिन्हित दस राज्यों को लेकर आयी चेतावनी से स्पष्ट हो जाता है। भ्रष्टाचार किस कदर फैल चुका है यह डी.एच.एल.एफ. के पैंतीस हजार करोड़ के घपले के सामने आने से स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि यह कंपनी सत्रह बैंकों को चूना लगाने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी भी हड़प चुकी है। जबकि जमीन पर न कोई मकान बना और न ही कोई उसका लाभार्थी सामने आया। सब कुछ कागजों में ही घट गया। यही आशंका 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटे जाने के दावे से उभरी है। क्योंकि 130 करोड़ की कुल आबादी में 80 करोड़ के दावे के साथ हर दूसरा आदमी इसका लाभार्थी हो जाता है। जबकि व्यवहार में ऐसा है नहीं है। ऐसी वस्तु स्थिति के बाद भी जब ऐसा दावा सामने आता है कि अगले चालीस वर्ष भाजपा के ही है तो कई सवाल आ खड़े होते हैं। क्योंकि 2014 में जो लोकपाल लाये जाने के लिये अन्ना के नेतृत्व में कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पार्याय प्रचारित करने का आंदोलन हुआ था उसमें अच्छे दिन आने का सपना दिखाया गया था। इसके लिये यह कहा गया था कि जहां कांग्रेस को साठ वर्ष देश ने दिये हैं वहीं पर भाजपा को साठ महीने दे कर देखो। लेकिन अब इन साठ महीनों के बजाये साठ साल मांगे जा रहे हैं। बल्कि पूरे दम के साथ यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले साठ वर्ष भाजपा के हैं। यह एक ऐसा दावा है जो हर किसी को चौंका रहा है क्योंकि 2014 के मुकाबले आज सरकार हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर बुरी तरह असफल है। इस दौरान कि अगर कोई उपलब्धियां है तो उन में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत तीन तलाक खत्म करना और धारा 370 समाप्त करना। लेकिन इससे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा इसको लेकर कुछ भी सामने नहीं आया है। बल्कि समाज में आपसी भाईचारा कैसे समाप्त हो रहा है यह धर्म संसदों के आयोजन से लेकर नूपुर शर्मा तक के बयानों से स्पष्ट हो जाता है। यहां तक कि देश की शीर्ष न्यायपालिका भी इसके प्रभाव से बच नहीं पायी है। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन और आल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के मामलों में एक ही खंडपीठ के आये दो अलग-अलग फैसलों से स्पष्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि आज की सरकार भी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर चल रही है। फूट डालने के लिए धर्म से बड़ा और आसान साधन और कुछ नहीं हो सकता। विभिन्न धर्मो के लोग जब अपने अपने धर्म की सर्वश्रेष्ठता के दावों की होड़ में दूसरे को नीचा दिखाने की सारी सीमायें लांघ जायेगा तो अनचाहे ही सत्ता का शासन करने का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। आज शायद यही हो रहा है। इसलिए आदमी को उसकी रसोई का महंगा होना और बच्चे का बेरोजगार हो कर घर बैठना भी इस श्रेष्ठता के अहंकार ने आंख ओझल कर दिया है। जबकि यह एक स्थापित सत्य है कि देर सवेर हर आदमी सर्वश्रेष्ठता कि हिंसा से बहुत वक्त बचकर नहीं रह पायेगा।

निखत जरीनः युवा मुस्लिम महिलाओं की आइकॉन

गौतम चौधरी

जिस व्यक्ति को स्वयं को पीड़ित दिखाने की आदत हो जाती है वह हर सकारात्मक पक्ष को भी नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि यदि कोई स्वयं को ताकतवर और काबिल साबित करने कोशिश करे तो वह वाकई में वैसा ही बन जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारा मस्तिष्क एक सशक्त हथियार है, जो हमें किसी काम को करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य दुनिया की लड़ाई अपने आत्मबल से जितता है और आत्मबल खत्म हो जाने के बाद वह हार जाता है। अब तो विज्ञान भी इस बात के लिए सहमत हो गया है कि व्यक्तित्व के निर्माण में सोच का व्यापक प्रभाव पड़ता है। वैसे हालात, समाज तथा पूर्वाग्रहित नियम कायदों की इसमें अहम भूमिका होती है, किन्तु खुद के निर्माण में स्वयं से अधिक कोई भी अन्य वस्तु प्रेरित नहीं कर सकती है। यह दर्शन सफलता का सूत्र है, जिसने निखत जरीन साबित करके दिखाया है।

हाल ही में विश्व मुक्केबाजी में चौंपियन बनी हिन्दुस्तानी महिला, निखत जरीन ऐसी पांचवीं भारतीय महिला मुक्केबाज हैं, जिसने तुर्की के इस्तानबुल में संपन्न हुई विश्वस्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस जीत के साथ इस 25 वर्षीय महिला ने भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उनके साथ अन्य हस्तियों में मैरिकॉम, सरिता देवी, जैनी आरएल तथा लेखा केसी शामिल हैं। अपने जीवन के संघर्ष में निखत जरीन ने स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गयी कई प्रसिद्ध पंक्तियों से प्रेरणा प्राप्त की, जिसमें उन्होंने कहा है, ''अगर तुम स्वयं को कमजोर मानते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे और अगर तुम स्वयं को शक्तिशाली मानते हो तो तुम शक्तिशाली हो जाओगे''।

मुक्केबाजी एक ऐसा जोश से भरा खेल है जिसमें नाम कमाना इतना चुनौती भरा है कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। जरीन द्वारा प्राप्त की गयी इस जीत ने उसे मैरीकॉम जैसी महान मुक्केबाज की परछाई से बाहर ला खड़ा किया है। वह अपनी इस जीत को आगामी ओलंपिक खेलों में एतिहासिक जीत प्राप्त करने हेतु सीढ़ी के एक पायदान के तौर पर देखती है। जिसे अभी तक कोई भी भारतीय प्राप्त नहीं कर पाया है। जरीन को यह सफलता अनेक सेघर्षो के बाद मिली है। उन संघर्षो में से एक उनके कंधे पर लगी गंभीर चोट भी शामिल है, जिसके कारण जरीन एक वर्ष के लिए खेल के मैदान से दूर रही। अपने ही समाज के द्वारा अस्वीकार किये जाने से लेकर विश्व चौंपियनसीप बनने तक की निखत जरीन की कहानी में पुनः लौटने का बल, आत्म विश्वास तथा स्वयं को इसके काबिल मानना शामिल है। आज वे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक हैं, जो महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और सबसे जरूरी वे अल्पसंख्य समुदाय के लोगों के लिये एक सबक है, जो आजकल पीड़ित होने का रोना रोते रहते हैं।

वर्ष 2019 के एक आंकड़े के अनुसार मुस्लिम महिलाएं भारत की कुल आबादी का 6.9 प्रतिशत है। अपनी इस विशेष संख्या बल होने के बावजूद मुस्लिम महिलाओं को आम तौर पर उत्पीड़ित, सतई हुई तथा अनपढ़ के तौर पर देखा जाता है। हम मुस्लिम महिलाओं के प्रति होने वाले वर्ताव को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो उनके अपने समुदाय तथा संपूर्ण समाज द्वारा किया जाता है। इतना सब कहने के बाद मुस्लिम महिलाओं को अपनी परिस्थितियों के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। उन्हें एक अलग व्यक्ति के तौर पर अपनी कीमत समझनी होगी। स्वयं को सम्मान देना होगा और सभी कठिनाइयों के बावजूद कठोर परिश्रम करना होगा ता कि वे समाज की जिम्मेदार सदस्य बन सके।

तेलांगाना प्रांत के हैदराबाद शहर स्थित एक रूढ़िवादी इलाके में रहने वाली निखत जरीन के पिता जमील को अक्सर उनके रिश्तेदार अपनी बेटी के छोटे परिधान यानी निक्कर पहन कर खेलने की इजाजत देने के लिये जिल्लतें सहनी पड़ती थी। वाकायदा वह आज भी जारी है। वे सभी कठिनाइयों से जुझते हुये जमीर ने अपनी बेटी निखत को अपने सपने पूरा करने की इजाजत दी तथा निखत ने भी अपने पिता का सिर नीचा नहीं होने दिया।

निखत की कहानी हमें बताती है कि केवल मुस्लिम महिलाओं को ही नहीं अन्य समाज की महिलाओं को गैरजरूरी और रूढ़िवादी अवरोधों को तोड़ना होगा। उन्हें अपनी आरामतलवी से बाहर निकलना होगा और स्वयं को पहचानने के लिये शिक्षित होना होगा। निखत जरीन की भांति लक्ष्य सिर्फ खेल में आगे निकलना नहीं है। बल्कि इसका एक मात्र लक्ष्य उसकी इस यात्रा से प्रेरणा लेनी चाहिये, जो उसने अपने सपनों को पाने के लिये पूरी की। उसका संघर्ष सचमुच हमारे लिये प्रेरणादायक है। केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए ही नहीं अन्य महिलाओं को भी इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। यह शांति से सामाजिक क्रांति का सूत्र है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत : हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों ने कोच्चि की पांच दिवसीय सफल यात्रा की

छात्रों ने स्थानीय व्यंजनों, संस्कृति और केरल राज्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में जाना

आजादी का अमृत महोत्सव – एक भारत श्रेष्ठ भारत के हिस्से के रूप में, शिमला (हिमाचल प्रदेश) के 50 विद्यार्थियों ने हाल ही में कोच्चि (केरल) की यात्रा की। 50 विद्यार्थियों में 25 छात्र-छात्राएं शिमला, ऊना और उसके आसपास के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी थे। इनमें 13 लड़के और 12 लड़कियां थीं। बाकी 25 विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान (यूआईटी), हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के बी. टेक विद्यार्थी थे। इनमें 15 लड़के और 10 लड़कियां थीं। उनके साथ चार शिक्षक भी थे। टीम ने 28 जून से 3 जुलाई 2022 तक कोच्चि में विभिन्न स्थानों का दौरा किया। एससीएमएस कोचीन स्कूल ऑफ बिजनस मेजबान संस्थान था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हिमाचल प्रदेश और केरल युग्मित राज्य हैं।

सरकार की अनूठी पहल, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में यह टीम कोच्चि में थी। इस विनिमय कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश के छात्रों ने चेंडामंगलम हथकरघा बुनकर सहकारी समिति का दौरा किया और चलाकुडी में रसा गुरुकुल रसोई में सांभर जैसे स्थानीय व्यंजन को पकाने में हाथ आजमाया।

यात्रा के आखिरी दिन, विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के समग्र शिक्षा केरल (एसएसके) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों राज्यों के शैक्षणिक संस्थानों के बीच एक बैठक में भी हिस्सा लिया और कलामस्सेरी में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत की।

कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, टीम ने प्रसिद्ध एएसआई स्मारकों और स्थानीय संग्रहालयों का भी दौरा किया जैसे, एडापल्ली में केरल इतिहास का संग्रहालय, एर्नाकुलम में दरबार हाल आर्ट गैलरी, त्रिपुनिथुरा (थ्रिप्पुनिथुरा) में हिल पैलेस संग्रहालय और थेवारा में केरल लोक कथा संग्रहालय। इसके अलावा, स्थानीय कला और खेल के बारे में जानने के लिए कलारीपयट्ट (कलारीपयटू) का भी एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश के छात्रों ने भी केरल के छात्रों के सामने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली ने इस यात्रा को सुविधाजनक बनाने में सहयोग किया।

जीएसटी– पांच साल में बेमिसाल

– श्रीमती निर्मला सीतारमण –

आज हमारे देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किये जाने के 5 साल पूरे हो गये हैं। इस पर पहली बार चर्चा वर्ष 2003 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर कार्यदल की रिपोर्ट में की गई थी और इस तरह से जीएसटी को मूर्त रूप देने में 13 साल का लंबा समय लग गया। वर्ष 2017 से ही जीएसटी को स्वाभाविक रूप से शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन शुरुआती समस्याओं से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड–19 वैश्विक महामारी द्वारा ढाये गये व्यापक कहर और इसके बेहद प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने के बाद यह काफी मजबूती के साथ उभर कर सामने आया है। इसका श्रेय जीएसटी परिषद को जाता है क्योंकि उसके जरिये ही केंद्र और राज्यों ने न केवल संकट का सामना करने के लिये, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को फिर से तेज विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए एक–दूसरे का हाथ बड़ी मजबूती के साथ थाम लिया। यह एक साथ मिलकर काम करने का ही सुखद नतीजा है कि भारत इस वर्ष के साथ–साथ अगले साल के लिए भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आया है, जैसा कि कई दिग्गज संस्थानों द्वारा अनुमान लगाया गया है।

वर्ष 2017 में भारत में लागू होने से बहुत पहले ही कई देशों ने जीएसटी व्यवस्था को अपने यहां बाकायदा अपना लिया था। लेकिन भारत में जीएसटी परिषद का स्वरूप अपने आप में अद्वितीय है। भारतीय राजनीति के अर्ध–संघीय स्वरूप, जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों को ही कराधान का स्वतंत्र अधिकार प्राप्त था, को देखते हुये इसके लिए एक अद्वितीय समाधान की नितांत जरूरत थी। विभिन्न आकार वाले राज्यों और विरासत में मिली अपनी कर प्रणाली के साथ विकास के विभिन्न चरणों से गुजर रहे राज्यों को जीएसटी के तहत एक साथ लाया जाना था। यही नहीं, राजस्व संग्रह के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के मामले में भी राज्य विभिन्न चरणों से गुजर रहे थे। इस तरह के हालात में एक संवैधानिक निकाय 'जीएसटी परिषद' और भारत के लिए अद्वितीय जीएसटी समाधान (दोहरा जीएसटी) की नितांत आवश्यकता महसूस की गई। कुछ अपवादों को छोड़ केंद्र और राज्यों दोनों के ही करों को जीएसटी में समाहित कर दिया गया। 17 अलग–अलग कानूनों का विलय कर दिया गया और जीएसटी के माध्यम से 'एकल कराधान' अमल में लाया गया।

भारत में जीएसटी परिषद ने जीएसटी के प्रमुख मुद्दों यथा दरों, छूट, व्यावसायिक प्रक्रियाओं और आईटीसी के संचालन इत्यादि पर राष्ट्रीय सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जुलाई 2017 में 63.9 लाख से भी अधिक करदाताओं ने जीएसटी को अपना लिया था। करदाताओं की यह संख्या जून 2022 तक दोगुनी से भी अधिक बढ़कर 1.38 करोड़ से ज्यादा हो गई है। 41.53 लाख से भी अधिक करदाता और 67 हजार ट्रांसपोर्टर ई–वे पोर्टल पर पंजीकृत हो गए हैं, जो प्रति माह औसतन 7.81 करोड़ ई–वे बिल सृजित करते हैं। इस सिस्टम को लॉन्च किये जाने के बाद से लेकर अब तक कुल 292 करोड़ ई–वे बिल सृजित हुए हैं, जिनमें से 42 प्रतिशत ई–वे बिल विभिन्न वस्तुओं की अंतर–राज्य ढुलाई से जुड़े हुए हैं। इस साल 31 मई को एक दिन में सबसे ज्यादा 31,56,013 ई–वे बिल सृजित किए गए थे।

औसत मासिक संग्रह 2020–21 के 1.04 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2021–22 में 1.24 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इस साल के पहले 2 महीनों में औसत संग्रह 1.55 लाख करोड़ रुपये रहा। यह उम्मीद उचित है कि यह निरंतर वृद्धि का रुझान जारी रहेगा।

जीएसटी ने सीएसटी/वैट व्यवस्था के तहत भारतीय राज्यों के बीच मौजूद कर मध्यस्थता को समाप्त कर दिया है। एक हस्तक्षेप करने वाली नियंत्रण प्रणाली, जिसमें सीमा चौकियों को शामिल करना और माल से लदे ट्रकों का भौतिक सत्यापन शामिल था, से बाधायें पैदा होती थीं, जिसके परिणामस्वरूप समय और ईंधन की हानि होती थी। परिणामस्वरूप कार्गो की आवाजाही के लिए लॉजिस्टिक, देश के भीतर भी, आवश्यक पैमाना और दक्षता हासिल नहीं कर पाया। माल की लागत में लॉजिस्टिक की लागत 15 प्रतिशत तक होने का अनुमान लगाया गया था।

आईजीएसटी के तहत और ई–वे बिल के साथ ऐसी कोई मध्यस्थता नहीं होने से, लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। विभिन्न साधनों वाली परिवहन व्यवस्था पर हमारे विशेष ध्यान और अब पीएम गति शक्ति के कारण इन लाभों का बढ़ना निश्चित है।

जीएसटी–पूर्व की व्यवस्था में, अधिकांश वस्तुओं पर, केंद्र और राज्यों की संयुक्त दरें 31 प्रतिशत से अधिक थीं। हालांकि, जीएसटी के तहत 400 से अधिक वस्तुओं और 80 सेवाओं की दरों में कमी हुई है। उच्चतम 28 प्रतिशत दर भोग और विलासिता की वस्तुओं तक ही सीमित है। 28 प्रतिशत की श्रेणी में कुल 230 वस्तुएं थीं, इनमें से करीब 200 वस्तुओं को कम दरों वाली श्रेणियों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उद्देश्य यह है कि उनके कर और अनुपालन का बोझ कम रखा जाए। समान रूप से, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण भी था कि वे आईटीसी के उद्देश्य के लिए आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकृत रहें। इस संदर्भ में, दो महत्वपूर्ण कदम उठाये गए थे: वस्तुओं के लिए छूट सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये और तिमाही रिटर्न तथा मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) योजना की शुरुआत, जिसमें 89 प्रतिशत करदाताओं को फायदा पहुंचाने की क्षमता थी।

शुरुआत के बाद से, जीएसटी का शासन आईटी आधारित और पूरी तरह से स्वचालित बना हुआ है। प्लेटफार्म के परिचालन के लिए पेशेवर रूप से प्रबंधित प्रौद्योगिकी कंपनी (जीएसटीएन का निर्माण सही दिशा में उठाया गया कदम था। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्षमताओं की निरंतर समीक्षा और उन्नयन ने प्रणाली को कार्यकुशल रखने में मदद की है।

सीमा शुल्क द्वारा स्वचालित आईजीएसटी रिफंड की प्रणाली और जीएसटी अधिकारियों द्वारा निर्यातकों को संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की वापसी ने निर्यात वस्तुओं और सेवाओं पर इनपुट करों को निर्बाध व समस्या मुक्त बना दिया है। उल्लेखनीय है कि जीएसटी मामलों से संबंधित अधिकांश मुकदमे आईटीसी तथा जीएसटी अधिकारियों को सम्मन जारी करने, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, वसूली के लिए संपत्ति की कुर्की आदि जैसे प्रवर्तन के विभिन्न पहलुओं से संबंध में प्राप्त शक्ति के मुद्दों से जुड़े हुए हैं। यहां तक कि मोहित मिनरल्स बनाम भारत संघ मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बहुचर्चित निर्णय में, न्यायालय ने जीएसटी की मूलभूत विशेषताओं को खारिज या परिवर्तित नहीं किया है।

24 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री रहे असीम दासगुप्ता 2000–2010 के दौरान राज्यों के वित्त मंत्रियों के उच्चाधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष थे। जीएसटी कानूनों का पहला सूत्रीकरण 2009 में किया गया था। 2 जुलाई 2017 को व्यापारिक मामलों से जुड़े एक समाचार पत्र को दिये गये एक साक्षात्कार में जीएसटी की महत्वपूर्ण विशेषताओं, जोकि आज भी बरकरार हैं, पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा था: ''राज्यों को कभी भी सेवा कर लगाने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। राज्य शुरू से ही महज संग्रह किये गये, सेवा कर का एक हिस्से के बजाय इस कर को लगाने की शक्ति की मांग करते रहे हैं। जीएसटी के जरिए इस संबंध में प्रावधान कर दिया गया है।''

उन्होंने कहा, 'उच्चाधिकार प्राप्त समिति राज्यों की स्वायत्तता के मामले में दृढ़ रवैया अपनाती रही है। प्रसंगवश जीएसटी परिषद, केन्द्रीय जीएसटी के मामले में संसद के लिए और राज्य जीएसटी के मामले में विधानसभाओं के लिए एक सिफारिशी निकाय है। तकनीकी रूप से, विधायिका इसे स्वीकार कर भी सकती है और नहीं भी। इस प्रकार, विधायिका की यह शक्ति नहीं छीनी गई है।''

महत्वपूर्ण बात यह है कि दासगुप्ता ने कहा, 'जहां तक दरों का सवाल है, राज्य और केन्द्र मिलकर दोनों के लिए एक तरह का एकल कर स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए, यह एक तरह से सहकारी संघवाद के हित में राज्यों और केन्द्र द्वारा किया गया एक आंशिक बलिदान है। जीएसटी, सेवा कर के मामले में राज्य को अतिरिक्त अधिकार दे रहा है। राज्य घरेलू उत्पाद में आधा हिस्सा सेवाओं का होता है।

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी के दो वर्ष पूरे होने पर अपने ब्लॉग में कहा था, ...जीएसटी उपभोक्ता और कर निर्धारिती, दोनों, के लिए अनुकूल साबित हुआ है। करदाताओं द्वारा दिखाई गई सकारात्मकता और निर्धारिती द्वारा तकनीक को अपनाये जाने की वजह से जीएसटी ने वास्तव में भारत को एक एकल बाजार में रूपांतरित कर दिया है।

हिमाचल में कृषि को बढ़ावा देने के लिए नवोन्मेषी प्रयास

शिमला। हिमाचल प्रदेश को कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने तथा किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की बेहतरी और कृषकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 628.52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

हिमाचल प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए षि पर निर्भर है और यह क्षेत्र लगभग 70 प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने फसल विविधिकरण पर विशेष बल दिया है ताकि षि उत्पादन में बढ़ोतरी और उत्पाद की गुणवत्ता के साथ–साथ षकों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी मिल सके।

राज्य में 9.44 लाख हेक्टेयर भूमि पर काश्त होती है तथा सकल घरेलू उत्पाद में इसका लगभग 13.62 प्रतिशत योगदान है। प्रदेश सरकार किसान परिवारों को विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा आधुनिक तकनीक के लाभ पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है। भूमि और जल जैसे प्रा तिक संसाधनों का इस प्रकार दोहन किया जा रहा है ताकि पर्यावरण संरक्षण को अपनाकर षकों का आर्थिक उत्थान सुनिश्चित बनाया जा सके।

षि में तकनीक के माध्यम से उच्च मूल्य वाली फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना आरम्भ की गई है। इस योजना का लक्ष्य फसल उत्पादन लागत को कम कर आय बढ़ाना, मृदा व मानव को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचाना है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 58.46 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

प्रदेश के 1 लाख 71 हजार 63 किसानों द्वारा 9 हजार 421 हैक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक पद्धति से खेती की जा रही है। वर्ष 2022–23 के लिए प्रदेश सरकार ने 50 हजार एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा 50 हजार किसानों को प्राकृतिक कृषक के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।

प्रदेश में फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिये हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना लागू की गई है। प्रदेश मे जाईका चरण–1 के सफल परिणामों को देखते हुए जाईका चरण–2 स्वीकृत की गई है। इसके अन्तर्गत 1010.13 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाया जा रहा है तथा कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण के लिए सरकार ने राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम लागू किया है। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को पावर टिल्लर व पावर वीडर, ब्रश कटर, रोटा वीडर, चौफ कटर, गेहूं थ्रैशर, मक्की शैलर, क्रॉप रीपर इत्यादि उपदान पर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत पिछले चार वर्षों में 74.88 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

प्रदेश में बेसहारा पशुओं, बन्दरों एवं अन्य जंगली जानवरों से फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। इसके बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को सौर ऊर्जा चालित बाड़ लगाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 80 प्रतिशत व समूह आधारित बाड़बंदी के लिए 85 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। पिछले चार वर्षों के दौरान इस योजना पर 186.28 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं तथा 9 हजार 846 किसान लाभान्वित हुए हैं।

प्रदेश में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी सरकार ने प्रवाह सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कुशल सिंचाई योजना, जल से कृषि को बल योजना, उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण एवं बोरवेल योजना आदि योजनाएं कार्यान्वित की हैं। इसके साथ–साथ विपणन की सुविधा हर किसान को घर के समीप मिल सके, इसके लिए जगह–जगह छोटे सब्जी संग्रहण केंद्र व मार्किट यार्ड बनाये जा रहे हैं। प्रदेश में कृषि विपणन कार्य के लिए राज्य स्तर पर कृषि विपणन बोर्ड गठित किया गया है, जिसके अन्तर्गत जिला स्तर पर 10 मंडियां क्रियाशील हैं तथा 54 उपमंडियां किसानों को विपणन सुविधा प्रदान कर रही हैं।

कृषक कल्याण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए खाद पर उपदान, कृषि से सम्पन्नता योजना, कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीकरण योजना सहित अनेक भी कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके साथ–साथ प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं भी सफलतापूर्वक लागू की जा रही हैं, जिनसे प्रदेश के किसानों की जिन्दगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और उपज में बढ़ोतरी से उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ हो रही है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से पौंग बांध विस्थापितों के लम्बित मामलों का शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राजस्थान के जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार पौंग बांध विस्थापितों के लम्बित मामलों का शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्र के विकास में सदैव ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पौंग बांध और अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से प्रदेश के लोगों ने विस्थापन का दर्द झेला है। पौंग बांध के निर्माण के दृष्टिगत 16,352 विस्थापित हिमाचलियों के पुनर्वास के लिए राजस्थान में 2.25 लाख एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी। उन्होंने कहा कि इनमें से केवल 8,713 विस्थापितों को भूमि/मुरब्बा उपलब्ध करवाया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कानून एवं व्यवस्था, आन्तरिक सुरक्षा, सीमा संबंधी मामले और अन्तरराज्यीय जल संबंधी मामलों की चर्चा करने के लिए आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भाग लिया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 7.19 प्रतिशत है, परन्तु राज्य को इसमें पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा परियोजना में प्रदेश की 1 लाख एकड़ से अधिक उपजाऊ भूमि और ब्यास नदी पर पौंग परियोजना के कारण डैहर में 65,563 एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है जबकि प्रदेश को इन जलाशयों से उत्पन्न बिजली और पानी के उचित उपयोग का अधिकार नहीं दिया गया है।

जय राम ठाकुर ने पिंजौर–बद्दी–नालागढ़ सड़क के फोरलेन संबंधी मामला भी उठाया है।

नशीले पदार्थों की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समस्या समाज के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में विशेष रूप से युवाओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ निरन्तर समन्वय बनाए हुए है। उन्होंने सभी राज्यों से इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने का संकल्प करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य के 585 दुर्गम गांव में दूरसंचार संपर्क का मामला भी उठाया।

मुख्यमंत्री ने वनों के संरक्षण में राज्य की प्रभावी भूमिका को रेखांकित करते हुए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में कुछ संशोधन करने के सुझाव दिए।

महिलाओं के हितों की रक्षा और उनके विरूद्ध अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की 60 दिनों के भीतर पूरी जांच सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षकों को आईटीएसएसओ पोर्टल पर नियमित रूप से निगरानी करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में अनुपालन दर 49.9 प्रतिशत थी जो वर्ष 2022 में बढ़कर 82.2 प्रतिशत हो गई है।

उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य के बद्दी–बरोटीवाला–नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में रेल संपर्क के लंबित मुद्दे के शीघ्र निवारण का भी आग्रह किया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ की गई कुछ सर्वोत्तम पहलो को साझा करते हुए जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य ने प्रशासन में अधिक पारदर्शिता लाने और आम आदमी की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए जन मंच शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया है और वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया है। इससे लगभग सभी वृद्धजन पेंशन पाने के हकदार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गंभीर मरीजों के लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक खेती–खुशहाल किसान योजना आरम्भ की है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1.71 लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से लाभान्वित कर 9421 हेक्टेयर क्षेत्र को इसके तहत लाया गया है।

उद्योग मंत्री ने एनआईसीडीपी के शीर्षस्थ निगरानी प्राधिकरण की बैठक में भाग लिया

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के शीर्षस्थ निगरानी प्राधिकरण की बैठक में भाग लिया।

बैठक में प्रदेश सरकार ने ऊना को अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी) परियोजना में

शामिल करने का आग्रह किया।

उद्योग मंत्री ने कहा कि ऊना जिला, बद्दी–बरोटीबाला–नालागढ़ (बीबीएन) क्षेत्र से सिर्फ 80 किमी की दूरी पर स्थित है तथा यह क्षेत्र प्रदेश के एक अन्य औद्योगिक जिला बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि जिला में सुदृढ़ सड़क एवं रेल नेटवर्क उपलब्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार पहले ही जिले में बल्क ड्रग पार्क और ईवी पार्क प्रस्तावित कर चुकी है।

उन्होंने कहा कि जिले में राज्य का पहला फूड पार्क और सात औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। इसके अलावा, जिले में लगभग 2000 एकड़ कुल भूमि के साथ कुछ आगामी औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऊना को एकेआईसी परियोजना के तहत शामिल करने का अनुरोध किया, जो न केवल ऊना जिले में औद्योगिक विकास को वांछित गति प्रदान करेगा, बल्कि पड़ोसी जिलों को भी आर्थिक प्रोत्साहन देगा, जहां राज्य की लगभग 50 प्रतिशत आबादी निवास करती है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास निगम सीमित (एनआईसीडीसी) के बीच एक संयुक्त उद्यम स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) प्रतिपादित किया जा रहा है और एनआईसीडीसी द्वारा किराए पर ली गई पेशेवर एजेंसी द्वारा साझा विकासात्मक ढांचे (ट्रंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर) के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि बीबीएन क्षेत्र में मेडिकल डिवाइसेस पार्क (300 एकड़) व डिफेंस पार्क (800 एकड़) जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को आधार बनाया गया है।

उद्योग मंत्री ने राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बीबीएन नोड में किए गए विकास के बारे में जमीनी सर्वेक्षण पूरा करने और बीबीएन क्षेत्र में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पार्सल के साथ पांच एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) चिन्हित करने के बारे में भी अवगत कराया।

बैठक में निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति भी शामिल हुए।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने "मिशन वात्सल्य योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए

शिमला/शैल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए 2009–10 से एक केन्द्र प्रायोजित योजना 'मिशन वात्सल्य' यानी बाल संरक्षण सेवा योजना शुरू की है। मिशन वात्सल्य का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना, हर क्षेत्र में विकास के लिए सहायता प्रदान करना, उनके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इको–व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें उनका पूर्ण विकास हो। इसके साथ ही राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को किशोर न्याय कानून 2015 के अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराने तथा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करना था। 'मिशन वात्सल्य' अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थागतकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार–आधारित गैर–संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है।

'मिशन वात्सल्य' के मुख्य कार्यों में संवैधानिक निकायों के कामकाज में सुधार लाना, सेवा प्रदान करने के ढांचे को मजबूत बनाना, संस्थागत देखभाल और सेवाओं के स्तर में वृद्धि करना, गैर–संस्थागत समुदाय आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करना, आपात स्थिति में पहुंच उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण शामिल हैं।

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने यहां इस योजना को लागू करने के लिए मंत्रालय के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। 'मिशन वात्सल्य' को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तौर पर केन्द्र तथा राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों के बीच निर्धारित लागत बंटवारा अनुपात के अनुरूप लागू किया जाएगा।

मंत्रालय ने 'मिशन वात्सल्य' योजना के विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं और राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों से वर्ष 2022–23 के लिए इस संबंध में वित्तीय नियम दिशा–निर्देश के आधार पर अपने वित्तीय प्रस्ताव और योजनाएं तैयार करने को कहा है। 'मिशन वात्सल्य' योजना के नियम एक अप्रैल 2022 से लागू होंगे।

अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के लिए वेबपोर्टल और वेबसाइट का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन की संशोधित योजनाओं, खेल विभाग की योजनाओं के लिए वेब पोर्टल (dbtyas-sports.gov.in) और राष्ट्रीय खेल विकास कोष वेबसाइट (nsdf.yas.gov.in) का भी शुभारंभ किया।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने खेल विभाग की इन योजनाओं को उपयोगकर्ता के लिए अधिक अनुकूल, उपयोग में आसान और पारदर्शी बनाने की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं एवं उनके प्रशिक्षकों के लिए नकद पुरस्कार की योजना, खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष (पीडीयूएनडब्ल्यूएफएस) और मेधावी खिलाड़ी पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने नागरिकों को सशक्त बनाने तथा सरकार एवं नागरिकों के बीच की खाई को कम करने, प्रणाली और सुविधाओं, समस्याओं व समाधानों का उपाय करने के साथ–साथ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम के रूप में इस विकास की सराहना की। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इन संशोधित योजनाओं से रिकॉर्ड समय में खिलाड़ियों को लाभ देने के लिए अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आयेगी।

ठाकुर ने कहा कि अब कोई भी खिलाड़ी अपनी पात्रता के अनुसार तीनों योजनाओं के लिए सीधे आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा, 'पहले खेल संघों/भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त भेजे जाते थे, जो प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में काफी समय लेते थे। कभी–कभी प्रस्ताव को स्वीकृत करने में 1–2 वर्ष से अधिक समय लग जाता था। नकद पुरस्कार की समय पर प्रस्तुति और बाद में अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए, आवेदक को अब विशेष आयोजन के समापन की अंतिम तिथि से छह महीने के भीतर नकद पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए तीनों योजनाओं में सत्यापन प्रक्रिया को काफी हद तक आसान कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षक को समय पर नकद पुरस्कार प्रदान करने के उद्देश्य से, योजना में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। डेफलिम्पिक्स के एथलीटों को भी पेंशन का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा, 'खेल विभाग ने इन योजनाओं में उपरोक्त सुविधाओं को लागू करने के लिए, खेल विभाग की उपरोक्त योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन करने में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए वेब पोर्टल dbtyas-sports.gov.in विकसित किया है।

ठाकुर ने कहा कि यह ऑनलाइन पोर्टल खिलाड़ियों द्वारा आवेदनों के वास्तविक समय का पता लगाने और उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के माध्यम से प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। आवेदकों द्वारा मंत्रालय को व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने की अब आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल को डीबीटी–एमआईएस के साथ भी जोड़ दिया गया है, जो भारत सरकार के डीबीटी मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खिलाड़ियों को सीधे उनके बैंक खातों में धन के हस्तांतरण को संभव बनाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पोर्टल न केवल समयबद्ध तरीके से सभी आवेदनों के त्वरित निपटान में विभाग की मदद करेगा, बल्कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की आवश्यक रिपोर्ट और खिलाड़ियों के डेटा प्रबंधन के लिए भी किया जाएगा। खिलाड़ियों की आवश्यकता व प्रचलित परिदृश्यों के अनुरूप समय–समय पर ऑनलाइन पोर्टल को और उन्नत किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विभाग ने 'राष्ट्रीय खेल विकास कोष' (एनएसडीएफ) के लिए एक समर्पित इंटरैक्टिव वेबसाइट nsdf.yas.gov.in भी विकसित की है। यह कोष देश में खेलों के प्रचार और विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी कंपनियों और व्यक्तियों आदि के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के माध्यम से प्राप्त योगदान पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से अब खिलाड़ी, खेल सुविधाओं और खेल आयोजनों के लिए व्यक्तिगत, संस्था और कॉर्पोरेट संगठन सीधे योगदान कर सकते हैं। एनएसडीएफ कोष का उपयोग लक्ष्य ओलंपिक पोडियम (टीओपी) योजना, प्रख्यात खिलाड़ियों और खेल संगठनों द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास आदि के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा,'यह समर्पित वेबसाइट न केवल खिलाड़ियों को बल्कि सीएसआर के लिए योगदानकर्ताओं को भी आसान और पारदर्शी पहुंच प्रदान करेगी। यह वेबसाइट देश में खेलों के विकास के लिए एनएसडीएफ को बड़ी सफलता दिलाने में हमारी मदद करेगी।

अनुराग ठाकुर ने स्वास्थ्य मंत्री से पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने आग्रह किया

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक व स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से भेंट करके देश में बनने वाले तीन बल्क ड्रग पार्क में एक की हिमाचल में स्थापना को मंजूरी देने व ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का आग्रह किया।

अनुराग ठाकुर ने कहा हिमाचल प्रदेश में अच्छी स्वास्थ्य सेवा के साथ रोज़गार के अवसर बढ़ सकें इस दिशा में मैं सदैव प्रयासरत हूँ। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने पूरे देश में तीन बल्क ड्रग पार्क देने का निर्णय लिया था, और 3000 करोड़ का प्रावधान पिछले बजट में किया था। हिमाचल क्योंकि फ़ार्मा हब है इसलिए इन तीन में से एक बल्क ड्रग पार्क हिमाचल में भी आ सके इसके लिए सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक व स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी से भेंट करके उनसे मैंने एक बल्क ड्रग पार्क को हिमाचल में लगाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया। मेरे अनुरोध को उन्होंने सकारात्मक रूप से लिया। इस बल्क ड्रग पार्क के बनने से ना सिर्फ़ पूरे हिमाचल में फ़ार्मा उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा बल्कि इस मंजूरी मिलने पर करीब 10 हजार लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। बल्क ड्रग पार्क बनने से यहा एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा जिसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा।

अनुराग ठाकुर ने स्वास्थ्य मंत्री से ऊना में बन रहे पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के जल्द निर्माण कार्य पूरा का आग्रह किया। उन्होने कहा कि ऊना के मलाहत में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर की मंजूरी कराई थी जिसका शिलान्यास 2019 में हो चुका है। ऊना में बन रहे इस पीजीआई का लाभ जल्द से जल्द प्रदेशवासियों को मिल सके इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने इसके काम में तेज़ी लाने व यथाशीघ्र निर्माण का भरोसा दिया है। ऊना के इस पीजीआई सेटेलाइट सेंटर का लाभ पंजाब और हिमाचल दोनों को हो पायेगा। 500 करोड़ से बनने वाले सेंटर में 125 से अधिक चिकित्सक एक हजार के करीब कर्मचारी तैनात होंगे। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो पाएंगे।

सरकार सेब बागवनों के लिये कार्टन व ट्रे की तुरंत समुचित व्यवस्था करे:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाते हुए किसी भी आपदा से प्रभावित लोगों की तुंरत सहायता की जाये। उन्होंने बरसात से प्रभावित सड़को विशेषकर दूर दराज की ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को तुरंत बहाल करने को भी कहा है जिससे लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्रतिभा सिंह ने प्रदेश की सड़कों की खस्ता हालत पर चिन्ता जताते हुए कहा है कि चूंकि अब प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने वाला है ऐसे में माल ढुलाई करने वाले बड़े बाहन चालको को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे सेब की ढुलाई में विपरीत असर पड़ सकता है।

प्रतिभा सिंह ने सरकार से सेब बागवनों के लिये कार्टन व ट्रे की तुरंत समुचित व्यवस्था करने को कहा है। उन्होंने सेब पेकिंग सामग्री के बड़े दामों को कम करने की मांग करते हुए कहा कि सेब बागवनों को विपणन में कोई समस्या न हो, इसके लिए लेबर, ट्रांसपोर्ट व कार्टन बक्सों की समुचित व्यवस्था की जाए।

प्रतिभा सिंह ने कहा है कि बाढ़ व बरसात से किसानों व बागवनों व पशु पालकों को हुए नुकसान का आंकलन करते हुए प्रभावित लोगों को भी तुरंत राहत प्रदान की जाए।

सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की वार्षिक विवरणियां वेबसाइट पर उपलब्ध

शिमला/शैल। प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं को वर्ष 2021-22 की वार्षिक विवरणियां आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा डाउनलोड करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट www.himkosh.nic.in. पर उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट पर सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) विवरणियां के लिंक पर क्लिक करें। उन्होंने सभी डीडीओ को उपलब्ध करवाए गए पासवर्ड को सुरक्षा के लिए बदलने का आग्रह किया। यदि किसी डीडीओ को पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो वह 0177-2804430 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

उन्होंने सभी डीडीओ से अनुरोध किया कि अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी कर्मचारियों की वर्ष 2021-22 की जीपीएफ विवरणियों के अथशेष को अपने वेतन बिल रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टी करने के उपरान्त सभी कर्मचारियों को यथाशीघ्र प्रदान करके इस कार्यालय को सूचित करें।

प्रवक्ता ने सभी सबसक्राइबर व डीडीओ से आग्रह किया कि अपनी वार्षिक जीपीएफ विवरणियों में दर्शाए गए आंकड़ों से स्वयं को सन्तुष्ट कर लें यदि उन्हें इसमें कोई त्रुटि लगे तो वार्षिक जीपीएफ विवरणी की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर प्रधान महालेखाकार कार्यालय की वेबसाईट www.aghp.cag.gov.in. में शिकायत एवं सुझाव दर्ज करें या agaehimachalpradesh/cag.gov.in पर ई-मेल करें। उन्होंने डीडीओ से यह भी आग्रह किया कि वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी कर्मचारी द्वारा लिए जाने वाले आहरण को भी इसी विवरणी के आधार पर स्वीकृत करें।

एच आर टी सी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अदायगी के लिए 110 करोड़ रुपये जारी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पिछले कुछ वर्षो से लम्बित डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) तथा लीव इनकैशमेंट बिलों की अदायगी के लिए प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम को 110 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे निगम के 1143 पेंशनर्ज लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मार्च महीने में आयोजित बैठक में पेंशनर्ज कल्याण मंच के पदाधिकारियों ने इस मामले के बारे में उन्हें अवगत करवाया था।

जय राम ठाकुर ने कहा कि निगम ने इस वर्ष अप्रैल माह के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन जारी की है, जो पूर्व में 6 से 7 महीने के विलम्ब से जारी होती थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 में हिमाचल पथ परिवहन निगम को वेतन और पेंशन की अदायगी के लिए 674 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि यह राशि पूर्व में दी गई राशि से लगभग दोगुनी है।

सरकार की योजनाओं को लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका:अपर महानिदेशक पीआईबी

शिमला/शैल। सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने और विकास के एजेंडे को मजबूत करने के लिए मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । यह बात अपर महानिदेशक (एडीजी) पत्र सूचना कार्यालय, चण्डीगढ़ राजेन्द्र चौधरी ने नाहन में आयोजित वार्तालाप के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पीआईबी की पहुँच राष्ट्रीय तथा प्रदेश की राजधानियों के पत्रकारों तक सीमित न रहकर जिला तथा खण्ड स्तर पर कार्य करने वाले मीडिया कर्मियो तक भी पहुँचे।

तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता पर बल देते हुए एडीजी पीआईबी चंडीगढ़ ने खबर की प्रमाणिकता की पुष्टि के लिए पीआईबी फैक्ट चैक प्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी तथ्य की पुष्टि करने के लिए पीआईबी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। साथ ही जिन खबरों की अभी तक पुष्टि की गई है उनकी भी जानकारी पीआईबी के पीआईबी फैक्टचेक ट्विटर हैंडल पर प्राप्त की जा सकती है।

मीडिया कार्यशाला (वार्तालाप) के दौरान उपस्थित मीडिया संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा योजनाओं की फीडबेक मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने में पत्रकारिता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उन्होंने कहा कि समाचार तथ्य पर आधारित हों तथा संवाददाताओं को आधारहीन और सनसनीखेज समाचारों को प्रेषित करने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनैतिक गतिविधियों को आम जनता तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर डा. अजय पाठक ने आयुष्मान भारत, टीबी उन्मूलन तथा नशा निवारण, जिला लोक सम्पर्क अधिकारी सिम्पल सकलानी ने सूचना प्रसार में मीडिया की भूमिका, प्रधानाचार्य डाइट ऋषि पाल शर्मा ने सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा नेहरू युवा केन्द्र के जिला युवा अधिकारी अनिल डोगरा ने फिट इंडिया तथा स्वच्छ भारत अभियान विषय पर विस्तृत जानकारी दी।

उपनिदेशक पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ हितेश रावत ने मुख्य अतिथि का स्वागत तथा मंच संचालन किया जबकि क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी पत्र सूचना कार्यालय चण्डीगढ अहमद खान ने उपस्थित प्रतिभागियों का धन्यवाद किया।

इस अवसर पर जिला में कार्यरत समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजीटल मीडिया के संवाददाताओं के अतिरिक्त पत्र सूचना कार्यालय चण्डीगढ से तनवीर खीलजी और पवन कुमार भी उपस्थित थे।

इग्नू ने वैदिक अध्ययन में मास्टर डिग्री के साथ 16 नए कार्यक्रम किए शुरू

शिमला/शैल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2022 सत्र के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र स्तर के 16 नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों में परिधान बिक्री, स्मार्ट सिटी विकास एवं प्रबंधन, जैंडर साईस, जैंडर इन लॉ, वैदिक गणित आदि छः माह की अवधि के प्रमाण पत्र स्तर के कार्यक्रम शामिल हैं। मास्टर डिग्री स्तर के कार्यक्रमों में हिन्दी व्यावसायिक लेखन और वैदिक अध्ययन शामिल हैं जबकि स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों में- अमेरिकी साहित्य, ब्रिटिश साहित्य, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, औद्योगिक विकास, अंग्रेजी में नया साहित्य, उपन्यास, वास्तुशास्त्र, भारत से लेखन तथा हाशिए से लेखन आदि शामिल हैं। ये सभी कार्यक्रम इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, शिमला से सीधे संचालित किए जाऐंगे। उक्त कार्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी इग्नू वैबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 निश्चित की गई है।

इग्नू शिमला के क्षेत्रीय निदेशक डॉ.जोगिन्द्र कुमार यादव ने पीआईबी को बताया कि युनिवर्सिटी जुलाई 2022 सत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बी.ए., बी. कॉम, बी.एस.सी. तथा कुछेक डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। प्रवेश एवं पुनः पंजीकरण के लिए लिंक इग्नू की वैबसाइट www.ignou.ac.in. पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए इग्नू के किसी भी नजदीकी अध्ययन केन्द्र से या इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, शिमला के दूरभाष संख्या 0177-2624612 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रैजन्टेशन देने से ही जीत सुनिश्चित हो जायेगी

- क्या शांता और धूमल मार्गदर्शक की भूमिका से बाहर आयेंगे
- मुख्य सूचना आयुक्त फूड कमिश्नर और लोक सेवा आयोग में होने वाली नियुक्तियां भी महत्वपूर्ण संकेतक होगी

शिमला/शैल। पिछले दिनों भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हैदराबाद में दो दिन बैठक हुई। इस बैठक के बाद यह वक्तव्य आया है कि आने वाले तीस-चालीस वर्ष भाजपा के ही होंगे। स्वभाविक है कि इस बैठक के बाद यह तो बयान आना नहीं था कि देश महंगाई और बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान है तथा पार्टी ने सरकार से इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने को कहा है। इसी वर्ष गुजरात और हिमाचल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन भी कर चुकी है। लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ है। जबकि इस आश्य के समाचार लगातार छपते रहे हैं। हिमाचल में नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में कोई भी कदम शायद इसीलिये नहीं उठाया जा सका है क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा इसी प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। जेपी नड्डा का पूरा समर्थन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ है। यह सब जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार अब मार्गदर्शक की भूमिका तक ही रह गये हैं यह भी व्यवहारिक रूप से सभी जानते हैं। नड्डा-जयराम के धूमल के साथ कितने मधुर रिश्ते हैं यह भी जगजाहिर है। बल्कि जिस ढंग से निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, प्रकाश राणा को पार्टी में शामिल करवा कर धूमल के निकटस्थों रविन्द्र रवि तथा गुलाब सिंह ठाकुर को साइडलाइन किया गया उससे इन सियासी रिश्तों पर मोहर लग गई है। हिमाचल में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर उठती हुई अटकलों को नड्डा के कारण ही मन्त्री मण्डल में फेर बदल यहां तक कि मन्त्रियों के विभागों में बदलाव तथा संगठन में भी चर्चाओं के बावजूद कोई बदलाव न हो पाना सब कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम ही लगता आया है। बल्कि अब तो सत्ता में पुनः वापसी हो पाने या न हो पाने की भी पहली जिम्मेदारी नड्डा के ही नाम लगने वाली है। क्योंकि जयराम सरकार के कामकाज से जनता कितना खुश है इसका फतवा तो चार नगर निगमों और फिर चार उप चुनावों के परिणामों से सामने आ ही चुका है। दीवार पर इस साफ लिखे को भी पढ़ कर नजरअन्दाज कर देने की ताकत नड्डा के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। इस परिदृश्य में राज्य सरकार के कामकाज पर हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने दी गयी प्रैजैन्टेशन को प्रदेश के नेतृत्व और नड्डा के फैसले पर मोहर लगवाना माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इतने खुले समर्थन के बाद भी सरकार सत्ता में वापसी कर पाती है या नहीं। यह सवाल इस परिदृश्य में इसलिये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी चुनाव के लिए तीन से चार माह का समय शेष है। फिर इसी दौरान सी आई सी, फूड कमिश्न और लोक सेवा आयोग में नियुक्तियां होनी है। यह नियुक्तियां पार्टी के नेताओं में से न होकर दूसरे वर्गो में से होनी है। इन नियुक्तियों में यह देखना काफी रोचक और संकेतक हो जाता है कि कौन लोग नियुक्त हो पाते हैं। कई अधिकारी तो केंद्र में जाने के जुगाड़ भिड़ाने में लग गये हैं। अभी सूचना आयोग में जिस तरह से अन्तिम क्षणों में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति रुक गयी है उसको लेकर भी कई चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ हलकों में तो मुख्य सचिव को हटाने की भी अटकलें चल पड़ी हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव द्वारा सूचना आयोग और फूड कमीशन के लिये आवेदक होने पर भी कई विश्लेषकों को हैरत है। क्योंकि प्रधान मुख्य सचिव से अधिक विश्वस्त मुख्यमंत्री का और कोई नहीं होता। फिर लोक सेवा आयोग के लिये भी एक दर्जन के करीब आवेदन आ चुके होने की चर्चा सचिवालय के गलियारों में कहीं भी सुनी जा सकती है। बल्कि प्रदेश के डीजीपी का नाम ही संभावितों में माना जा रहा है। चर्चा है कि यहां पर कई विश्वस्तों के हितों में आपसी टकराव होगा। यह नियुक्तियां भी सरकार के सत्ता में वापसी के कई संकेत सूत्र छोड़ जायेगी यह तय है। फिर आने वाले दिनों में जब मुख्यमंत्री से लेकर नीचे मंत्रियों तक के विभागों की कारगुजारीयां आम जनता के सामने आयेंगी तब पता चलेगा कि महंगाई और बेरोजगारी के दश झेलती हुई जनता इसी सरकार की वापसी के लिये कितना तैयार हो पाती है।

राष्ट्रपति चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट कहां जायेगा

पार्टी के भविष्य के प्रति यह एक बड़ा संकेत होगा

शिमला/शैल। आम आदमी पार्टी ने अब हिमाचल इकाई में अठारह प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर दी है। लेकिन अभी भी प्रदेश इकाई शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों से आगे नहीं बढ़ पायी है। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य में भी कैसे आगे बढ़ेंगे इसका भी कोई ब्लू प्रिन्ट अभी जनता के सामने नहीं आ पाया है। संसाधन कहां से आयेंगे इसके लिए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने का दावा केजरीवाल और सिसोदिया अपनी रैलियों में करते रहे हैं। लेकिन प्रदेश के किस विभाग में किस मंत्री या अधिकारी के साये तले कितना भ्रष्टाचार हुआ है इसमें भी अभी तक कोई चिन्हित नहीं हो पाया है। अब तक जो भी प्रचार- प्रसार हो रहा है वह एक सामान्य हवा पार्टी के पक्ष में बनाने से अधिक कुछ नहीं लग रहा है। इसी से पार्टी की नीयत को लेकर आशंकाएं उभरनी शुरू हो गयी है। क्योंकि पार्टी का बहुचर्चित दिल्ली मॉडल मुफ्ती की घोषणाओं से अधिक कुछ नहीं है। इस मुफ्ती की घोषणाओं ने देश की आर्थिकी पर कितना और क्या असर डाला है इसका खुलासा आर.बी.आई. की जून माह में आई रिपोर्ट से सामने आ चुका है। इसी सब पर केंद्र के अधिकारी प्रधानमंत्री को एक बैठक में आगाह कर चुके हैं। इस बैठक में अधिकारियों ने साफ कहा था कि यदि मुफ्ती की घोषणाओं पर समय रहते नियंत्रण न पाया गया तो कुछ राज्यों के हालात श्रीलंका जैसे कभी भी हो सकते हैं। ऐसे दस राज्यों की आर.बी.आई. सूची भी जारी कर चुका है और श्रीलंका में हालात क्या हो गये हैं यह सब के सामने है। इस परिपेक्ष में आज राष्ट्रपति चुनाव एक ऐसा अवसर है जिसमें राजनीतिक दलों की नीयत और नीति दोनों का खुलासा जनता के सामने आ जायेगा। क्योंकि आज जो दस राज्य श्रीलंका जैसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं उसके लिये पिछले 8 वर्षो में केंद्र सरकार की जो नीतियां रही हैं वह भी बहुत हद तक जिम्मेदार रही हैं। ऐसे इस राष्ट्रपति चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता पक्ष और कौन सी विपक्ष के उम्मीदवार के साथ खड़ी होती है इससे पता चल जायेगा कि कौन परोक्ष-अपरोक्ष में सत्ता पक्ष के साथ है या उसके विरोध में। इस समय आप की दिल्ली और पंजाब दो राज्यों में सरकारें हैं। राज्यसभा में आप के सांसद हैं। लेकिन आप ने अभी तक अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया है कि वह एनडीए के साथ हैं या विपक्ष के साथ हैं। केजरीवाल विपक्ष की सर्वदलीय बैठक से गायब रहे हैं। ऐसे में यदि आप एनडीए के पक्ष में वोट करती है तो उसका असर हिमाचल में भी आप के भविष्य पर पड़ेगा। यह माना जायेगा कि आप हिमाचल में केवल भाजपा की मदद करने के लिये ही मैदान में आ रहा है। वैसे यह आरोप बहुत पहले से लगना शुरू हो गया है कि आप उन्ही राज्यों में सक्रिय भूमिका निभाता है जहां पर भाजपा के साथ कांग्रेस सीधे मुकाबले में होती है। हिमाचल में भी भाजपा को कांग्रेस से खतरा है और इसलिए आप यहां चुनाव लड़ने की बात कर रही है।